प्रोवोकेशन ट्रैप : ईरान-अमेरिका विवाद

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

25 दिसम्बर, 2020

ईरान को इराक में अपने हस्तक्षेप पर रोक लगाना चाहिए और बिडेन प्रशासन को कूटनीति को फिर से शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए।

रविवार को बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमले हुए, जिसे अमेरिकी सैन्य अधिकारीयों ने एक दशक में सबसे सुरक्षित क्षेत्र पर सबसे बड़ा हमला कहा है और इसके बाद इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रशासन के वरिष्ठ नेताओं ने ईरान की ओर इशारा करते हुए कहा है कि यह रॉकेटों की आपूर्ति करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका के रडार-निर्देशित रक्षात्मक प्रणालियों ने इस राकेट को मार गिराया है। ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि 'यदि एक भी अमेरिकी मारे जाते हैं तो वे इसके लिए ईरान को जिम्मेदार मानेंगे।'

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पहले से ही ईरान-अमेरिका संबंध नाजुक स्थिति में है। विदित हो कि दोनों देशों के संबंधों में दरार 2018 में एकतरफा रूप से ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर होने के बाद हुई, जिसके बाद ईरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया गया था। स्थिति यह हो गयी थी कि जब ट्रम्प चुनाव हार गये तब उन्होंने कथित तौर पर ईरान पर हमले शुरू करने के लिए विकल्प खोजना शुरू कर दिया था, लेकिन मंत्रिमंडल के सहयोगियों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया।

हालाँकि, अब ट्रम्प जल्द ही व्हाइट हाउस से बाहर निकलेंगे और अगले राष्ट्रपति, जो बिडेन, जिन्होनें परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने का वादा किया है, राजनयिक प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के अवसर की तलाश कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के हमले दोनों देशों को एक खुले संघर्ष में ले जाने की पूरी संभावना को व्यक्त करते हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने ईरान के लिए पूरी तरह से एक अलग नीति अपनाई। इसने संयुक्त राष्ट्र के प्रमाणन के बावजूद अमेरिका को परमाणु समझौते से बाहर कर दिया। ईरान अपनी शर्तों के अनुरूप था, फिर भी तेहरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू किया। व्यावहारिक रूप से, ट्रंप ने ईरान की दृष्टि से इजरायल और सऊदी अरब के साथ गठबंधन किया था। ट्रम्प के कार्यकाल ने इजरायल को अपने गुप्त और उल्टे कार्यों को चलाने का अवसर दिया।

2018 में, इजरायल के जासूसों ने ईरान के अंदर एक गोदाम में एक साहसी मिशन को अंजाम दिया और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित हजारों दस्तावेज चुरा लिए। ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों पर हमले होने की संभावना काफी बढ़ गयी। सीरिया में, जहां ईरान ने बशर अल-असद की सरकार का समर्थन करते हुए मिलिशिया तैनात की है, इजराइल ने ईरानी ठिकानों पर बमबारी जारी रखी है।

जब अमेरिका ने इस साल जनवरी में ईरानी जनरल कासिम सोलीमनी की हत्या कर दी, तो अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि इराक की राजधानी में ड्रोन हमले ने अमेरिका की राह में फिर से अवरोध का निर्माण किया है। लेकिन ईरान ने कई सैनिकों को घायल करते हुए इराक में अमेरिकी सैन्य शिविरों पर जवाबी मिसाइल हमले करना जारी रखा और उसके बाद से, इराक में ईरान समर्थक शिया मिलिशिया ने ग्रीन जोन में मिसाइल हमले शुरू कर दिए जिसमें दूतावास और इराक के अंदर अमेरिकी आपूर्ति लाइनों को बार-बार निशाना बनाया गया।

अमेरिका ने पहले अपने दूतावास के कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया, बसरा में वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया और इराक में सैनिकों को कम करने का फैसला किया। यदि अमेरिका-ईरान संबंध अब एक विस्फोटक रूप ले रहा है, तो प्राथमिक जिम्मेदारी ट्रम्प के पास है। अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाने के अलावा, ईरान ने सीधे या परोक्ष रूप से, पिछले दो वर्षों में खाड़ी में तेल सुविधाओं और टैंकरों पर हमला किया था।

इस महीने की शुरुआत में, जेद्दा से एक टैंकर पर कथित तौर पर यमन के ईरान समर्थित हौदी विद्रोहियों द्वारा हमला किया गया था। अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा ईरान के प्रभाव को कम करने के प्रयासों का मुकाबला करने का ईरान पर काफी दबाव है। पिछले महीने के अंत में, एक शीर्ष वैज्ञानिक, मोहसिन फाखरीजादे की हत्या ईरान के अंदर ही कथित रूप से इजरायली एजेंटों द्वारा कर दी गयी थी। लेकिन बदला लेने की चाह में ईरान को उकसावे के जाल में नहीं फसना चाहिए।

किसी भी परिस्थिति में, राजनयिक मिशनों पर हमलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उसे इराक में मिलिशिया समूहों पर लगाम लगाना चाहिए जिसका ईरान समर्थन करता है। हांलाकि, इस हमले ने ईरान को एक स्थिति में ला खड़ा किया है जहाँ यदि वह जवाबी कार्रवाई नहीं करता है, तो इससे यह प्रतीत होगा कि ईरान की शक्ति क्षीण हो रही है और इसे देखते हुए इसके प्रतिद्वंद्वी इस पर हमले और तेज कर सकते है और यदि इरान जवाबी कार्रवाई करता है, तो यह टकराव को और बढ़ा सकता है, जो शायद एक विनाशकारी युद्ध में तब्दील हो सकता है। ईरान को इराक में अपने हस्तक्षेप पर रोक लगाना चाहिए और बिडेन प्रशासन को कूटनीति को फिर से शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. ईरान परमाणु सौदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. इसके तहत ईरान 8 साल तक किसी भी तरह की मिसाइल तकनीक तो खरीद सकता था, लेकिन 15 साल तक ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता था।
2. इसके तहत ईरान को अपने कुल संवर्धित यूरेनियम का 98% हिस्सा नष्ट करना था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2 दोनों **(b)** केवल 2
(c) केवल 1 **(d)** न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of 'Iran Nuclear Deal': -

1. Under this, Iran could buy any type of missile technology for 8 years, but Iran could not make nuclear weapons for 15 years.
2. Under this, Iran was to destroy 98% of its total enriched uranium.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Both 1 and 2 **(b)** Only 2
(c) Only 1 **(d)** Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गये प्रतिबंधों के कारण ईरान के साथ भारतीय व्यापार और संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें। (250 शब्द)

Q. Discuss the effects on Indian trade and relations with Iran due to sanctions imposed on Iran by US. (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।